प्रदेशभर से मिली जानकारी में खुलासा

कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 366 शिक्षकों की मौत

भोपाल/इंदौर •
डीबी स्टार

कोरोना तेजी से पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है। इसकी लहर पहली की तुलना में काफी खतरनाक साबित हो रही है। सरकार संक्रमण को नियंत्रण में लाने की हरसंभव कोशिश कर रही है इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। इसमें स्वास्थ सेवाओं के अलावा पुलिस और अन्य सरकारी-निजी संस्थान के लोग भी शामिल हैं। अगर स्कूल शिक्षा विभाग की ही बात करें तो कोरोना पीड़ितों में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, प्राचार्य और शिक्षकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में विभाग के 366 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या 334 शिक्षकों की संख्या है। इनमें 19 कर्मचारी, 11 प्राचार्य और 2 अधिकारी शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 1809 कर्मचारियों में से 1633 शिक्षक हैं। इनमें 80 प्राचार्य, 73 कर्मचारी और 23 अधिकारी शामिल हैं। इंदौर में कोरोना से एक प्राचार्य और 8 शिक्षक सहित 10 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। 180 कर्मचारी कोविड पीड़ित हैं। डीबी स्टार में समाचार प्रकाशित होने के बाद विभाग ने सभी जिलों से मृतक और बीमार कर्मचारियों की संख्या मंगाई थी, जिसमें ये आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेशभर के कर्मचारियों में कोरोना से मौत और संक्रमितों में शिक्षकों की संख्या अधिक है। इसका कारण यह है कि शिक्षकों को कोरोना आपदा सेंटर, कोरोना सर्वे और टीकाकरण कार्य में ड्यूटी लगाई गई है, जबकि उन्हें वह सुरक्षा साधन नहीं दिए गए हैं, जो अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध होते हैं।

Badri Gautam

एंकर स्टोरी

शिक्षकों को कोराना योद्धा घोषित करने और इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की

प्रदेश में 334 शिक्षकों की कोरोना से मौत, 1633 हुए संक्रमित

शहर प्रतिनिधि, भोपाल । प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी विभाग कोरोना के कहर से अछूता नही है। प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, प्राचार्य और शिक्षकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी प्रदेश में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक सहित 366 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 334 शिक्षकों की संख्या है। साथ ही 19 कर्मचारी, 11 प्राचार्य और 2 अधिकारी शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों में भी 1809 में से 1633 शिक्षक कोरोना संक्रमित हैं। साथ ही 80 प्राचार्य, 73 कर्मचारी व 23 अधिकारी शामिल है। प्रदेश भर में कोरोना से मौत और संक्रमितों में शिक्षकों की संख्या अधिक है। इसका कारण यह है कि शिक्षकों को कोराना आपदा सेंटर, कोरोना सर्वेऔर टीकाकरण कार्य में ड्यूटी लगाई गई है। वहीं शिक्षक संगठनों ने विरोध जताते हुए मांग की है कि शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। उनके इलाज में आर्थिक मदद की जाए। इस संबंध में मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता सुभाष सक्सेना ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वर्तमान में कोराना महामारी का भयावह स्थिति है । इस स्थिति में प्रदेश के हजारों नियमित शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग के शिक्षक संक्रमित हो गए हैं। इनमें सैकड़ों शिक्षक व अध्यापक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वर्तमान में कोरोना का इलाज बहुत महंगा हो गया है। इसकी दवाइयां इंजेक्शन, ऑक्सीजन इत्यादि बहुत महंगे दामों में मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को इलाज कराने के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसके निराकरण के लिए हमारी मांग है कि प्रदेश में जो नियमित शिक्षक हैं उनके भविष्य निधि खाते से 24 घंटे के अंदर दो लाख रुपये निकालने के निर्देश दिए जाए एवं अध्यापकों को 24 घंटे के अंदर चिकित्सा एडवांस के रूप में दो लाख रुपये उनके खाते में दिए जाए और उस राशि को आसान किस्तों में वापस ले लिया जाए।

इन जिलों में सबसे अधिक शिक्षक संक्रमित

जिला	संक्रमित	शिक्षक	मौत	शिक्षक
भोपाल	259	235	10	8
इंदौर	180	164	9	7
उज्जैन	110	100	51	51
छिंदवा.डा	106	103	35	33
सिवनी	135	129	27	24
बालाघाट	86	82	9	9
होशंगाबाद	90	77	9	8
सागर	39	32	29	27
विदिशा	38	38	8	8
राजगढ़	51	43	4	5
नरसिंहपुर	51	42	7	7

भोपाल में सबसे अधिक शिक्षक संक्रमित

भोपाल जिले में सबसे अधिक 235 शिक्षक संक्रमित हैं। वहीं आठ शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं उज्जैन में 110 संक्रमितों में से 51 शिक्षकों की मौत हुई है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अधिक सुदृढ़ होंगे

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया 5.50 करोड़ का बजट

शहर संवाददाता, भोपाल। अब प्रदेश के 275 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अधिक सुदृढ़ होंगे। इसके लिए आवासीय विद्यालयों के लिए राशि दी गई है। जिससे कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो बालिकाओं को आदर्श विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को तीन लाख रुपये के हिसाब से राशि वितरित की है। विभाग की ओर से आवासीय विद्यालयों में फर्नीचर से लेकर मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने के लिए साढ़े पांच करोड रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए विद्यालयों से जिन संसाधनों की कमी थी, उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई थी। ज्ञात हो कि इन विद्यालयों में 75 फीसदी अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं और 25 फीसद गरीबी रेखा से नीजे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला होता है। प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में 150 से 300 तक सीटें रहती हैं।

मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा: विभाग के पास शिकायत मिली थी कि आवासीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कई आवासीय विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल नहीं है तो कुछ में स्वच्छ शौचालय की कमी है। वहीं कुछ में बिजली और फर्नीचर कमी है। इसे सदृढ़ करने के लिए विभाग ने बजट स्वीकृत किए हैं। साथ ही इसे जल्द से जल्द सुधारने के आदेश दिए हैं।

Badri Gautam

दिवंगत कर्मचारियों को योद्धा मानकर बीमा राशि और पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए

नगर प्रतिनिधि, भोपाल। कोरोना संक्रमण के कारण दिवंगत होने वाले मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मानकर बीमा राशि और पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि वर्तमान में कोरोना योद्धा योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार की नीति दोहरी है और इसमें एकरूपता जरूरी है। न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र सिंह तिवारी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि कोविड 19 जैसी महामारी में सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी संक्रमण का शिकार हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्कूलों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी भी शामिल हैं। फिर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण से दिवंगत होने वाले कर्मचारियों की संख्या हजारों में हैं और इनमें लगभग 500 कर्मचारी शिक्षा विभाग के हैं। सरकार की कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान कर परिजनों को प्रदान करने का नियम है। योजना में भेदभाव यह किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों को वंचित रखा गया है। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। चूंकि 2005 के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए जिन कर्मचारियों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, उन्हें 50 लाख के साथ पेंशन का भी लाभ दिया जाना चाहिए। तिवारी ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों को सरल बनाने और संक्रमित कर्मचारियों के परिजनों को जल्दी नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। संक्रमित कर्मचारियों को चिकित्सा उपचार का भी लाभ दिया जाना चाहिए।

न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ ने सीएम को लिखा पत्र

Badri Gautam

एमपी बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला आज

12वीं की परीक्षाएं जून में ऑफलाइन कराने के संकेत

जागरण, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते एमपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 26 अप्रैल को फैसला होगा। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने सोमवार दोपहर बाद अफसरों की बैठक बुलाई है। परमार ने कहा, प्रदेश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षाएं करवाकर बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया, सरकार ने 12वीं की परीक्षाएं जून माह में कराने की तैयारी की है। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? इसे लेकर सोमवार को अंतिम फैसला हो सकता है। परीक्षा ऑफलाइन ही होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी तरह, 10वीं की परीक्षा ऑनलाइन होंगी या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा, इसे लेकर भी बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जनरल प्रमोशन किसी भी हाल में नहीं देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 30 अप्रैल के बजाय जून के पहले सप्ताह से आयोजित करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन यह परीक्षाएं किस पद्धति से होंगी, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है।

Badri Gautam

सूत्रों का कहना है, मंत्री परमार सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के लिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित करने के पक्ष में है। इसे लेकर बैठक में निर्णय होगा। बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा को रद्द कर आतंरिक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। पहले के परीक्षा कार्यक्रम में 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षा आयोजित होना थी, जिन्हें जून तक स्थगित कर दिया गया था।

दसवीं-बारहवीं को लेकर आज हो सकता है फैसला, स्कूल शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक माह के लिए स्थगित हुई माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा दसवीं-बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला सोमवार को हो सकता है।

इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने दोपहर बाद अफसरों की बैठक बुलाई है। विभागीय सूत्रों की मानें तो सरकार 12वीं की परीक्षाएं जून माह में कराने पर विचार कर रही है, इसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन इस पर अंतिम मुहर इस बैठक में लगेगी। इसके साथ ही 10वीं की परीक्षा ऑनलाइन होंगी या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा, इसे लेकर भी बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

Badri Gautam

असमंजस में विद्यार्थी और अभिभावक

एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आज हो सकता है फैसला

स्टार समाचार | भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर कोई निश्चित फैसला नहीं होने कारण अभिभावक, शिक्षक व बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों की कक्षाओं में पूरी तरह जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। सोमवार को इसको लेकर स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें आंतरिक मूल्यांकन या ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जनरल प्रमोशन किसी भी हाल में नहीं देंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के मद्देनजर 30 अप्रैल की बजाय जून के पहले सप्ताह से आयोजित करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन यह परीक्षाएं किस पद्धति से होंगी, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है। सीबीएसई ने दसवीं की परीक्षा को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। अब प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग मप्र बोर्ड की कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मंथन कर रहा है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ-साथ अभिभावकों और विद्यार्थियों को परीक्षा की चिंता सताने लगी है। हालांकि विभाग सोमवार को इस संबंध में एक बैठक फिर आयोजित कर रहा है। इसमें मंत्री की उपस्थिति में विचार विमर्श किया जाएगा।

Badri Gautam

जून तक स्थगित की थी परीक्षा

अधिकारियों ने बताया कि दसवी में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन और बारहवीं में ऑनलाइन पेपर देकर ओपन बुक पैटर्न पर कराने पर अंतिम फैसला लिया जाना है, लेकिन अभी इस बात पर भी असमंजस है कि दसवीं के आंतरिक मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं या टेस्ट लिए गए हैं या नहीं। ज्ञात हो कि प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूल पहले ही बंद हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नौवीं से बारहवीं तक की वार्षिक व प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी बंद कर दी गई है। वहीं पहले के परीक्षा कार्यक्रम में दसवीं की परीक्षा 30 अप्रैल से बारहवीं की परीक्षाएं एक मई से आयोजित होनी थी। उन्हें जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

एमपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षा को लेकर अभी भी असमंजस में विद्यार्थी

माशिमं की हेल्पलाइन पर 25 दिन में 25 हजार स्टूडेंट्स, पैरेंट्स ने किए काल, एक ही सवाल-जनरल प्रमोशन मिलेगा या परीक्षा होगी

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

''मैम! कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 10-12वीं की परीक्षाएं होंगी या फिर जनरल प्रमोशन मिलेगा।... परीक्षाएं होंगी, तो किस पैटर्न पर होंगी।'' कुछ इस तरह के सवाल स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की हेल्पलाइन में कॉल करके पूछ रहे हैं।

ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण फैलने के कारण बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक नया शेड्यूल नहीं बताया गया है। ऐसे में मंडल की हेल्पलाइन नंबर 18002330175 पर कॉल्स की संख्या बढ़ गई है। अभी हेल्पलाइन शुरू हुए 25 दिन ही हुए हैं, लेकिन कॉल की संख्या 25 हजार से ऊपर पहुंच गई है। आलम यह है कि प्रत्येक दिन एक हजार से अधिक स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स यहां काल कर जानकारी ले रहे हैं। सामान्य दिनों में 300 से 500 कॉल रोजाना आते थे।

तीन शिफ्टों में चार-चार काउंसलर कर रहे समाधानः माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन तीन शिफ्टों में संचालित की जा रही है। पहली शिफ्ट में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चार लोग और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक चार लोग काउंसलिंग कर रहे थे। सुबह 8 से रात 8 बजे तक तीन शिफ्टों में 12 काउंसलर सवालों का जवाब दे रहे हैं।

Badri Gautam

बीते सालों में कॉल की स्थिति

2018 में 1 लाख 6 हजार कॉल आए।
2019 में 1 लाख 23 हजार कॉल आए।
2020 में 2 लाख 35 हजार काल आए।
1 अप्रैल 2021 से 25 दिन में : 25 हजार कॉल आए।

80% विद्यार्थी और 20 फीसदी पैरेंट्स व टीचर पूछते हैं सवाल

हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स में 80 फीसदी कॉल विद्यार्थियों के होते हैं। 10 फीसदी शिक्षक और 10 फीसदी अभिभावक कॉल कर रहे हैं। वहीं हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स में 70 फीसदी कॉल एकेडमिक व कॅरियर से संबंधित होते हैं।

पैरेंट्स को बच्चों की चिंता

कोरोना काल में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित किए जाने से स्टूडेंट परेशान हैं। वह पूछ रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं, यदि होंगी तो किस पैटर्न पर होंगी। पैरेंट्स को इस कोरोना की भयावहता को देखते हुए बच्चों की चिंता सता रही है।
डॉ. हेमंत शर्मा, प्रभारी, एमपी बोर्ड हेल्पलाइन

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नि:शुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

इंदौर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी में शामिल होने के इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन वर्ग के पात्र उम्मीदवारों से नि:शुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक ने स्नातक परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की हो, मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो। आवेदक ने पूर्व में किसी भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो। प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी होगा इच्छुक उम्मीदवार Email-petcjabalpur@gmail.com पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, स्नातक अंक सूची की छायाप्रति 30 अप्रैल तक भेज सकते हैं। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8889609588 पर संपर्क कर सकते हैं।

Badri Gautam

एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन 30 तक

इंदौर। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्राचार्य, उप प्राचार्य, पीजीटी और टीजीटी की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अप्रैल तक जमा किए जा सकते हैं। ईंटीएसएसई 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन, शैक्षिक योग्यताएं, शिक्षण अनुभव और अन्य पात्रता मानदंड आदि के संबंध में सूचना बुलेटिन https: recruitment.nta.nic.in पर उपलब्ध है।

Badri Gautam

ऑनलाइन कक्षाओं में नई पाठ्य सामग्री का अभाव

भोपाल(नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना महामारी के कारण पहली से आठवीं कक्षा के स्कूल इस सत्र में भी खुल नहीं पाएं। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 13 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है।

पिछले सत्र की तरह इस साल भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों लिए रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। एक अप्रैल से राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से रेडियो व दूरदर्शन पर नए सत्र का शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन पाठ्य सामग्री पुरानी होने से बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। विभाग की ओर से रेडियो व टीवी पर नई पाठ्य सामग्री तैयार नहीं की गई है। इस कारण पढ़ाई नीरस हो रही है। राज्य शिक्षा केंद्र के मीडिया प्रभारी अमिताभ अनुरागी ने बताया कि 30 अप्रैल तक पिछले सत्र के पाठ्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद नई सामग्री को तैयार किया जाएगा। अभी कोरोना के कारण नए कार्यक्रम तैयार नहीं हो पाए हैं। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक गतिविधियां रेडियो पर सुबह 10 से 11 बजे और शाम पांच से 5.30 बजे तक एवं दूरदर्शन पर दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक संचालित की जा रही हैं। रेडियो पर सुबह पहली से आठवीं के लिए पाठ्यपुस्तक आधारित हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों में और शाम को खेल, योग, कला, म्यूजिक पढ़ाया जाता है।

Badri Gautam

किड्स कॉर्नर

जोखिम उठाएं, गलतियां होंगी और इसी तरह आप आगे बढ़ सकेंगे - मैरी टाइलर मूर

हर गलती कुछ सिखाती है, खर्च के मामले में बच्चे को दें थोड़ी छूट

रोहित गाजभिये
संस्थापक, फाइनेंसपीयर

ज्यादातर माता-पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे भूल, गलतियां और विफलता जैसा कोई अनुभव करें। पैसों के मामले में तो कतई नहीं। हकीकत यह है कि इन गलतियों से ही लोग महत्वपूर्ण सबक लेते हैं। यह मायने नहीं रखता है कि बच्चे ने पैसे से संबंधित कोई गलती की है। यह ज्यादा मायने रखता है कि बच्चे ने उस गलती से क्या सीखा है और उसको लेकर उसकी प्रतिक्रिया क्या थी।

Badri Gautam

माता-पिता उठा सकते हैं ये चार कदम

1 गैर-जरूरी खर्चों के बारे में बात करें

बच्चों को यह समझाने का प्रयास करें कि उनकी कौन सी खरीद जरूरी है और किस चीज की इच्छा टाली जा सकती है। बच्चे को पॉकेट मनी दें। उसे ही यह तय करने दीजिए कि कौन सी खरीदारी जरूरी है और क्या उसके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जैसी गैर-जरूरी चीजों के लिए पर्याप्त बचत है? ऐसा करने पर बच्चों के खर्च में गलती की आशंका कम हो जाती है।

2 बच्चे से गलती होने की गुंजाइश छोड़ें

बच्चे को खर्च करने की अनुमति दें। एक बार जब वह समझ जाएगा कि उसकी कोई खरीदारी गैर-जरूरी थी और इसलिए वह एक गलती थी, तो यह उसके लिए बड़ा सबक होगा। असल में पैसे से संबंधित गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। याद रखें, खर्च के मामले में होने वाली गलती बचपन में ही समझना बड़े होने पर उसी तरह की गलती करने से बेहतर है।

3 गलती हो जाने पर बच्चे को समझाएं

हालांकि माता-पिता अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हैं कि बच्चा खर्च के मामले में गलती न करे। ऐसी गलतियों के लिए बच्चे को डांटना आम तौर पर पहली त्वरित प्रतिक्रिया हाती है। लेकिन, इस मामले में यह समझना जरूरी है कि आपका बच्चा सीख रहा है और देख रहा है कि उससे कहां गलती हुई है। बच्चे से बात पर चर्चा करें कि उसने जो गलती की उससे क्या सीखा।

4 अच्छी खरीद की सराहना करें

गलतियों से सीखने के अलावा, अगर किसी बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी किताबें या अपनी पढ़ाई से संबंधित किसी चीज पर खर्च की है तो माता-पिता को चाहिए कि वे उनके इस तरह के अच्छे फैसलों के लिए उनकी सराहना करें। हो सकता है कि उसने परिवार के किसी सदस्य के लिए बतौर गिफ्ट कोई काम की चीज खरीदी हो तो भी वह तरीफ का हकदार होता है। ऐसा करने से बच्चा सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित होगा।

परिजनों को अब तक नहीं मिली अनुग्रह राशि

प्रतिनिधि | जबलपुर

शासन द्वारा मृत्यु के शिकार कर्मचारियों के परिजनों को तत्काल 50 हजार की अनुग्रह राशि दी जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोरोना महामारी के शिकार हुए शिक्षकों एवं कर्मचारियों के परिजनों को अभी तक यह राशि नहीं दी गई है। ऐसे आरोप मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के योगेन्द्र दुबे ने लगाए हैं। उनका कहना है कि जिले में दर्जनों शिक्षकों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुकी है और कई दिन बीतने पर भी उनके आश्रितों को यह राशि नहीं मिलने से उन्हें समस्याएँ झेलनी पड़ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन परिजनों द्वारा अपने मृत सदस्यों के इलाज एवं देहांत के बाद वाले संस्कारों में बड़ी धनराशि खर्च होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा चुकी है। संगठन के अर्वेन्द्र राजपूत एवं अवधेश तिवारी ने शासन से उचित कार्रवाई की माँग की है।

Badri Gautam

दी जाए कैशलेस की सुविधा

मप्र शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल अग्रवाल का कहना है कि जिले के कई सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारी गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं। इस दौरान कैशलेस सुविधा न होने से उनका समुचित इलाज तक नहीं हो पा रहा है और ओपन हार्ट सर्जरी, कैंसर, लकवा तथा कोरोना संक्रमण का उपचार भी कर्ज लेकर करवाना पड़ रहा है। संगठन के जिला अध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया एवं पीएन तिवारी ने शिक्षकों, सहायक शिक्षकों एवं अध्यापकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की माँग शासन से की है।

पेंशनर्स एसोसिएशन ने किया स्मरण

कोरोना महामारी से पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी डीके तिवारी का निधन होने पर संगठन द्वारा उनका स्मरण किया गया। इस दौरान एचपी उरमलिया एवं शेषमणि पांडे मौजूद थे। पी-2

बोर्ड परीक्षाएँ रद्द होने के बाद सीबीएसई द्वारा स्कूलों से जुटाई जा रही सालाना जानकारी

परफॉर्मेंस के हिसाब से बनेगा दसवीं के छात्रों का रिजल्ट

निज प्रतिनिधि | जबलपुर

Badri Gautam

कोरोना महामारी के चलते केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा 10वीं हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बाद अब दसवीं के छात्रों के रिजल्ट की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत बोर्ड द्वारा सीबीएसई स्कूलों से छात्रों के सालाना परफॉर्मेंस की जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों को एक फॉर्मेट भेजा गया है, जिसमें छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, असानइमेंट और अन्य तरह की सभी 15 बिन्दुओं पर जानकारियाँ माँगी गई हैं। इसमें छात्रों का नाम, उम्र, अभिभावक, जाति पूर्व परीक्षा का परिणाम के साथ स्कूल टेस्ट में शामिल होने से तिमाही-छमाही परीक्षाओं में शामिल होने की जानकारी स्कूलों को बोर्ड तक भेजनी होगी। पी-4

जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ 65 शिक्षक चंडालभाटा स्थित कोरोना कमांड सेंटर में करेंगे ड्यूटी

नई पाठशाला • अब कोरोना पेशेन्ट्स से फीडबैक लेंगे शिक्षक

निज प्रतिनिधि | जबलपुर

कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से उनकी तबियत के साथ अन्य बातों का फीडबैक लेने के लिए जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ 65 शिक्षक दमोहनाका स्थित कोरोना कमांड सेंटर में बैठेंगे। ये आदेश 26 अप्रैल से लागू होगा, जिसके संबंध में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षकों को उनकी ड्यूटी के संबंध में जानकारी देते हुए समय पर पहुँचने का आदेश जारी किया है। दो पालियों में लगने वाली ये ड्यूटी दोपहर 2 से रात 8 बजे तक अलग-अलग समयों पर लगाई गई है। पी-4

संकट काल में मदद पहुँचाने आगे आया कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम

पूरे दिन घनघनाता है फोन, अधिकारियों से बात करके लोगों की समस्या का किया जा रहा समाधान

कार्यालय प्रतिनिधि | जबलपुर

Badri Gautam

आपदा की इस घड़ी में जब लोग परेशान हैं और उन्हें कहीं से कोई मदद या फिर सही जानकारी देने वाला नहीं मिलता ऐसे में कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में पदस्थ कर्मचारी आगे आये हैं। जैसे ही किसी का फोन पहुँचता है तत्काल ही अधिकारियों से संपर्क बनाकर लोगों को सहयोग किया जा रहा है। पूरे दिन कंट्रोल रूम का फोन घनघनाता रहता है और कोशिश यह की जाती है कि हर किसी को यहाँ से सहायता मिले। ऐसा ही एक फोन पहुँचा कि उनके पिता गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती हैं और अब उन्हें डिस्चार्ज कराया गया है तो उनसे 2 लाख 70 हजार रुपये का बिल माँगा जा रहा है। 1 लाख 30 हजार वे जमा कर चुके हैं। अधिकारियों को बताया गया तो उन्होंने मौके पर पहुँचकर अस्पताल प्रबंधन और मरीज के परिजनों से बात की और समस्या का समाधान कराया। कंट्रोल रूम में इसके साथ ही प्रतिदिन कई फोन अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं अन्य मदद के लिए आते हैं। नोडल अधिकारी सृष्टि प्रजापति के निर्देश पर कर्मी 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं। जबलपुर के साथ ही आसपास के जिलों से भी फोन पहुँचते हैं जिनकी भी हरसंभव मदद की जाती है। कंट्रोल रूम में फिलहाल उमाशंकर अवस्थी, अनिल मरावी, उमेश यादव, राकेश मून के साथ ही आधा दर्जन कर्मचारी तैनात रहते हैं। पी-4

कोविड के मरीजों को योग से ठीक करने की कवायद

स्कूलों के योग गुरू अब कोविड के मरीजों को देंगे ट्रेनिंग

योग प्रशिक्षकों को होम आसाइलेटेड मरीजों को सिखाना होगा योग

जागरण, रीवा। योग से निरोग कार्यक्रम के तहत अब योग गुरू कोविड मरीजों को योग शिखाएंगे। मोबाइल से योग की जानकारी देंगे। योग के जरिए ही उन्हें जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सभी वालंटियर का आनलाइन आदेश जनरेट किया जा रहा है।

कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने योग का सहारा लिया है। सभी योग गुरु यानि प्रशिक्षकों को कोविड मरीजों को योग सिखाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सभी का आदेश जनरेट किया जाएगा। सभी योग गुरुओं को होम आसोलेटेड मरीजों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। योग प्रशिक्षक फोन पर ही सभी मरीजों से संपर्क करेंगे। उन्हें योग के लिए मोटीवेट करेंगे। यदि उनकी हां हुई तो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हालांकि योग गुरु दिए गए गाइड लाइन से हट कर कुछ भी नहीं करेंगे। जिन योग को सिखाने के निर्देश हैं, उसकी की जानकारी भी उन्हें देनी होगी। योग के लिए राजी होने वाले मरीजों को लगातार तीन दिनों तक फोन पर ही ट्रेनिंग देनी होगी।

यह है आदेश

आयुष मंत्रालय से सभी योग प्रशिक्षकों के आदेश जनरेट हो गए हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पर उन्हें होम आइसोलेटेड पेशेंट से नार्मल काल द्वारा बात कर योग प्रशिक्षण लेने के लिए सहमति एवं समय की जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार ही प्रशिक्षण दिया जाए। जो प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते, उन्हें जबरदस्ती नहीं करना होगा। दिए गए प्रशिक्षण के अनुक्रम में ही बात करना पड़ेगा। अन्य किसी प्रकार का सुझाव इवाइयां की जानकारी अपने तरफ से अलग से न दें। तीन दिनों तक प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।

यह योग क्रियाएं सिचानी होगी

आयुष मंत्रालय के अनुसार 10 मिनट तक सामान्य योग क्रियाएं सिखानी है। इसमें प्रार्थना 30 सेकंड, योग चालन, कंधी का चालन, उदर का चालन 2 मिनट, ताड़ासन, अर्धचक्रासन 1-1 मिनट, शशकासन 1 मिनट, भुजंगासन 1 मिनिट, पवनमुक्तासन 1 मिनिट, अनुलोम विलोम, नाड़ीशोधन प्राणायाम 1 मिनिट, ध्यान 1 मिनिट, संकल्प, शांति 30 मिनिट का योग कराना है।

स्कूल शिक्षा विभाग जुटाएगा जानकारी

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि डीईओ कार्यालय में एक नोउल अधिकारी होगा जो प्रशिक्षकों एवं होम आसोलेशन मरीजों की मैपिंग के लिए जिम्मेदार होगा। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा विभागीय संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला आयुष अधिकारी एवं संबंधित जिले के योग प्रशिक्षकों को सम्मलित करते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। मैपिंग का कार्य पांच चरण में किया जाएगा। माय गवर्नमेंट पोर्टल से स्वयंसेवकों की जिलेवार सूची राज्य स्तर से सीधे जिला शिखा अधिकारी के लॉगइन से विमर्श पोर्टल पर भेजी जाएगी। सार्थक पोर्टल से जिलेवार संक्रमित होम आइसोलेटेड किए गए मरीजों की सूची जिला आयुष अधिकारी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। इसी मरीजों की सूची को वाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी को सर्कुलेट किया जाएगा। प्रशिक्षक को 10 मरीजों के नाम उपलब्ध कराए जाएंगे। तीन दिन की ट्रेनिंग देने के बाद फिर 10 मरीजों की सूची दी जाएगी।

Badri Gautam

शिक्षक अध्यापक संवर्ग को वेतन के लाले

डीडीओ पॉवर नहीं मिलने से हालत खराब

जवा ब्यूरो । रीवा जिले के जवा विकासखंड सहित अन्य ब्लॉकों के अध्यापक शिक्षक संवर्ग का माह. मार्च 2021 से वेतन डीडीओ पावर्स समाप्त हो जाने के कारण लंबित पड़ा है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रान्तीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह जवा ने जानकारी देते हुये बताया कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल के स्थानांतरण उपरांत नवीन जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के प्रभार का दायित्व केपी तिवारी को सौपा गया है। जिन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडीओ पावर्स सम्बन्धी कार्यवाही के उपरांत आज तक नही दिया गया है। इसी परिपेक्ष्य में रीवा जिले के कई विकास खंडों में आहरण संवितरण अधिकारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी के डीडीओ पावर्स की भी समय सीमा समाप्त हो गई है। नवीन डीईओ साहब को भी अभी तक डीडीओ पावर प्रदान नहीं किए गए हैं। जिसके चलते जिला अंतर्गत कई विकास खंडों के विकास खंड शिक्षा अधिकारी के डीडीओ पावर्स रिन्यूवल नहीं हो पा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जवा के लगभग 500 सिरमौर के 200 सहित अन्य ब्लाकों के लगभग 2000 अध्यापक शिक्षक सम्वर्ग का वेतन माह मार्च से भुगतान होना लंबित है। जिससे कर्मचारियो को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है। और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मप्र के प्रमोद चतुर्वेदी, संजय सिंह, पुष्पेंद्र द्विवेदी, बालेंदु शेखर द्विवेदी, इंद्रलाल वर्मा आदि ने कलेक्टर रीवा से मांग की है कि नवीन जिला शिक्षा अधिकारी को डीडीओ पावर्स जारी कराएं, ताकि जिले के अध्यापक संवर्ग का वेतन भुगतान संभव हो सके।

Badri Gautam

दिवंगत सरकारी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मानते हुए

बीमा राशि, पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जाए

रीवा(नव स्वदेश)। कोविड-19 जैसे महामारी में सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी भी संक्रमण के शिकार हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्कूलों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के शासकीय कर्मचारी सम्मिलित हैं फिर भी लगातार सभी विभागों के सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी निरन्तर अपनी सेवाएं कोरोना महामारी में दे रहे हैं,कोरोना से दिवंगत होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग हजारों है जिसमें 500 के लगभग स्कूल शिक्षको,अध्यापकों की है,कोरोना से दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत 50 लाख रूपए के बीमा राशि का प्रावधान कर परिजनों को राशि प्रदान करने की नियमावली बनाई है, परन्तु गनीमत है कि इसमें भी भेदभाव किया गया स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों को इसके लाभ से वंचित रखा गया है जो सरासर अन्याय है सभी विभागों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसी तरह दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के साथ एक और भेदभाव किया गया है 2005 से शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ भी नहीं दिया गया है,जिन साथियों की मृत्यु कोरोना से हुई है चाहे वो किसी भी सरकारी विभागों से ताल्लुकात रखते थे चाहे स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के शिक्षक हो या राज्य शिक्षा सेवा के शिक्षक हो या पंचायत विभाग के अधीन कार्यरत अध्यापक संवर्ग सभी को सरकार कोरोना योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्रदान करें,और भले ही उनकी नियुक्ति 2005 के उपरांत हुई है, दिवंगत साथियों के परिजनों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जाएं सभी शासकीय कर्मचारियों को परिजनों सहित संक्रमित होने पर चिकित्सा उपचार का लाभ मिले तथा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधानों को सरल करते हुए सीधे दिवंगत साथियों के परिजनों को इसका लाभ शीघ्रता के साथ प्रदान किया जाएं कोरोना जैसी महामारी से दिवंगत साथियों के परिजनों के ऊपर पहाड़ जैसा टूट गया है,घर में एक कमाने वाले के चले जाने से उनके घरों में दसों आश्रितों के पास आर्थिक संकट खड़ा है, अभी संक्रमण काल में भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पूरे मुस्तैदी के साथ सेवाओं में तैनात है, इसलिए सरकार का दायित्व है कि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुएं जीवन के साथ आकस्मिक घटित होने वाली घटनाओं के प्रति भयमुक्त वातावरण प्रदान करे न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री से माग करता है कि जिस तरह सभी विभागों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कल्याण योजना का लाभ दिया गया है उसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएं, तथा कोरोना से दिवंगत सभी अधिकारी कर्मचारियों के आश्रितों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान किया जाएं तथा दिवंगत साथियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति नियमावली को सरलीकरण करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने के आदेश जारी किए जाएं। पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री अपने शासकीय सेवकों के प्रति उपरोक्त मांगों पर विचार करते हुए आदेश जारी कर लाभान्वित करेंगे।

Badri Gautam

लॉकडाउन में दिव्यांग कर्मचारियों को उपस्थिति में मिले छूट

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण संदीप रजक ने सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को जारी पत्र में कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न जिलों में लागू लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयीन उपस्थिति में छूट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों के संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए उन्हें विशेष कार्य होने पर ही कार्यालय बुलाया जाए और घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाए। कोरोना संक्रमण को केंद्र शासन द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले इन दिनों बहुत तेजी से देश प्रदेश में बढ़े हैं, हालांकि इनमें ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफी बढ़ी है। दिव्यांग जनों की सुरक्षा और संरक्षण के मद्देनजर केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

दसवीं के विद्यार्थियों का स्कूलों से मांगा ब्योरा, भेजा गया फार्मेट

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा को कोरोना संक्रमण के चलते निरस्त कर दिया था लेकिन अब बोर्ड परीक्षा परिणामों को लेकर तैयारी शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सीबीएसई द्वारा सभी स्कूलों से विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है। वहीं विद्यार्थियों की साल भर की गतिविधियों की जानकारियों की रिपोर्ट तैयार कर देने के लिए स्कूलों से कहा गया है जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

सभी स्कूलों को एक फार्मेट भेजा जा रहा है। इसमें सालभर हुए प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि की जानकारी मांगी गयी है। इसके आधार पर रिजल्ट की तैयारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार स्कूलों को इसके लिए 15 बदुओं का फार्मेट भेजा गया है जिसके आधार पर जानकारी भरकर देने के लिए कहा गया है। इसमें छात्रों की पूरी जानकारी जिसमें सेक्शनवार छात्रों का नाम, उम्र, पिता का नाम, जाति,

परिणाम की तैयारी

- **साल भर की गतिविधियों की मांगी गई रिपोर्ट**
- **सीबीएसई ने शुरू की रिजल्ट की तैयारी**

Badri Gautam

पूर्व परीक्षा का परिणाम की डिटेल्स स्कूलों को भेजना है। स्कूल के टेस्ट में शामिल होने से लेकर टर्म परीक्षा में शामिल होने की जानकारी भी देनी होगी। गौरतलब है कि जिले में करीब 30 से अधिक सीबीएसई स्कूल हैं। दसवीं कक्षा की परीक्षाएं एक माह पूर्व होने वाली थी जिसे रदद किया जा चुका है। स्कूलों की समस्या है कि लॉकडाउन के चलते शिक्षण संस्थान बंद है ऐसे में कैसे जानकारी को जुटाया जाए। कई स्कूलों में स्टाफ खुद ही संक्रमित है तो वहीं स्कूल आने से डर रहे हैं।

ऑनलाइन स्टडी से बच्चों को एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी भी बंद

ऐसे हालात में पैरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे बच्चों पर तनाव हावी न होने दें और सेहत का पूरा ध्यान रखें

परिचर्चा

भोपाल • डीबी स्टार

वर्तमान हालात में कहीं लॉकडाउन है तो कहीं कोरोना कर्फ्यू, इसके चलते सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर न हो इसलिए शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। यह लगातार दूसरी बार है कि बच्चे रेगुलर स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इससे वे संक्रमण से तो सुरक्षित हैं, लेकिन उन पर मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। वहीं होमवर्क, असाइनमेंट के ओवरलोड के कारण उनके पास खेलने का समय भी नहीं है। ऐसे में पैरेंट्स ध्यान दें कि बच्चे अनावश्यक तनाव लेकर न पढ़ें, वे खेले-कूदें भी।

शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है

कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर हुआ है। एक ओर ऑनलाइन क्लास का टेंशन, तो दूसरी ओर होमवर्क की चिंता। ऐसे में इन बच्चों की सेहत प्रभावित हो रही है। संक्रमण के डर से पैरेंट्स बच्चों को बाहर खेलने नहीं जाने दे सकते। जिस उम्र में उन्हें खेलने-कूदने और शैतानी करना चाहिए, तब कोरोना ने उन्हें घर में कैद कर दिया है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है। अब जरूरी है कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अभिभावक उनसे फिजिकल एक्टिविटी भी करवाएं

-अभिनेष कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर

एक्सरसाइज से बच्चा मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा

मां-बाप पहले बच्चों को मोबाइल-लैपटॉप इस्तेमाल करने से मना करते थे, लेकिन संक्रमण के चलते स्कूल-कॉलेज बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अधिकांश स्कूल ऑनलाइन ही पढ़ाई करवा रहे हैं। यही वजह है कि चाहकर भी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देना पड़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों की फिटनेस का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पढ़ाई और एग्जाम में टॉप करने का उन पर दबाव न बनाएं। उसे घर में ही योगा, साइकिलिंग, रस्सीकूद आदि चीजें करने को कहें। इन एक्सरसाइज से वह मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा।

-नीतू मिश्रा, टीचर

पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों का खेलना-कूदना भी जरूरी है

स्वस्थ दिमाग सही रूप में एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। आज संक्रमण के दौर में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन ही बेहतर और सुरक्षित माध्यम बन गया है। ऑनलाइन क्लॉस के बाद बच्चों को इतना होमवर्क और असाइनमेंट मिल जाता है कि उनका अधिकतर समय उसे पूरा करने में बीत रहा है। वे मानसिक रूप से इतना थक जाते हैं कि वे खेलना तक नहीं चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों का खेलना-कूदना भी जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर टीचर पढ़ाने के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करवाएं ताकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो।

-महेन्द्र मालवीय, इंजीनियर, कम्प्यूटर साइंस

ऑनलाइन क्लास से बच्चे पढ़ाई के प्रति उदासीन हो रहे

ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई के प्रति उदासीन हो रहे हैं। स्कूल जाने का बच्चों में उत्साह रहता था, लेकिन अब वह भी खत्म हो रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार 80 फीसदी बच्चों का सोने-जागने, नहाने-खाने तक का डेली रूटीन बिगड़ गया है। संक्रमण के चलते स्कूल के अलावा घर पर भी खेल गतिविधियां बंद हैं। ऐसे में कई बच्चे बीमार होने लगे हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चे घर पर ही रहकर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें। इससे उनमें मेंटल स्ट्रेस कम होने के साथ ऑनलाइन पढ़ाई से होने वाली थकान भी दूर होगी। इसका ध्यान बच्चों से ज्यादा पैरेंट्स को रखना होगा।

- प्रशांत दत्त, व्यवसायी

Basant Gautam

4 साल में सरकार ने 347 छात्रों को दिल्ली में कराई UPSC की कोचिंग

8.54 करोड़ खर्च करने के बावजूद एससी वर्ग का एक भी छात्र नहीं बन सका IAS

सीताराम ठाकुर ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

मप्र सरकार हर साल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी) में पास कराने के लिए उनकी कोचिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन बीते चार साल में इस वर्ग के एक भी छात्र का यूपीएससी में चयन नहीं हुआ। सरकार ने इस दौरान 347 छात्रों की कोचिंग पर 8.54 करोड़ रुपए विभिन्न कोचिंग संस्थाओं पर खर्च भी कर दिए, जबकि इन कोचिंग से अन्य वर्ग के छात्र हर साल आईएएस बन रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को विदेश की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि देश में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी) के लिए भी हर साल मप्र सरकार छात्रों का चयन कर उन्हें कोचिंग के लिए दिल्ली भेजती है। जिन उच्च स्तर की कोचिंग संस्थाओं में इन छात्रों को परीक्षा पूर्व तैयारी की कोचिंग कराई जाती है, उनमें से हर साल अन्य वर्ग ओबीसी, जनरल के छात्र आईएएस तो बन रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं। खासकर इस वर्ग के छात्र प्री परीक्षा क्वालिफाई और मेन परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिससे वे इंटरव्यू तक पहुंचते ही नहीं है, जिसके कारण सरकार का करोड़ों रुपए हर साल बेकार जा रहा है।

पीपुल्स समाचार
पड़ताल

फाइल फोटो

कोचिंग पर किस साल कितनी राशि खर्च

वर्ष	छात्रों का चयन	खर्च राशि
2016-17	93	264.12
2017-18	81	226.35
2018-19	89	282.97
2019-20	84	80.78
राशि		854.23
कुल छात्र		347

स्त्रोतः आदिम जाति विभाग -राशि लाख में

दिल्ली की इन संस्थाओं में कराई गई कोचिंग

दिल्ली की जिन संस्थाओं में इन छात्रों की कोचिंग कराई जाती है, उनमें बाजीराम एंड रवि इंस्टिट्यूट फॉर आईएएस, अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड, दृष्टि द विजन, कैरियर प्लस एजुकेशन संस्थान तथा श्रीराम आईएएस नई दिल्ली शामिल हैं।

इस साल भी कोचिंग से वंचित रहेंगे छात्र

कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में एक भी छात्र का चयन यूपीएससी की कोचिंग के लिए किसी भी छात्र का नहीं किया था और इस साल भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण किसी भी छात्र का चयन होने की संभावना नहीं है।

सरकार के प्रयास सफल नहीं हुए, आगे होंगे

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को यूपीएससी की कोचिंग कराने और उनके सफल होने के लिए सरकार ने एक-एक छात्र पर लाखों रुपए खर्च किए है, लेकिन सरकार के प्रयास सफल नहीं हुए। हमारी सरकार अब इस मामले में प्रयास तेज करेगी और अगले सालों में छात्र सफल होंगे।

कृष्णा गौर, विधायक, गोविंदपुरा

प्री और मेन परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते

जिन छात्रों का चयन यूपीएससी के लिए कर हम उन्हें दिल्ली भेजते हैं, उनमें से अधिकांश छात्र प्री परीक्षा और मेन परीक्षा क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, जिसके कारण वे इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते हैं। वर्ष 2018-19 के छात्रों की कोचिंग के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है, संभावना है कि एक-दो छात्र इस बार इंटरव्यू तक पहुंच सकें।

सुधीर कुमार जैन, अपर संचालक, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

Badri Gautam

हायर पेंशन के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

इंदौर/भोपाल | DBStar

प्रदेश में निजी कंपनियों, कारखानों, निगम मंडलों, सहकारी संस्थाओं और परिषदों में काम करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) हायर पेंशन मिलने में फिर लंबा अरसा लग सकता है। इसमें संभावित देरी की वजह यह है कि दो साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित ईपीएफ की हायर पेंशन से संबंधित 59 याचिकाओं पर सुनवाई फिर टल गई है। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक 22 अप्रैल को भी शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई। एसए बोबडे के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर होने के बाद नए सीजेआई नुतालपति वेंकट रमना ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। अब कोर्ट में नए सिरे से बेंच का निर्धारण होगा। उसके बाद ही सुनवाई संभव हो पाएगी। वर्तमान में सुनवाई कर रही बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अक्टूबर 2016 को दिए गए निर्णय पर भी विचार करने का निश्चय किया था।

Badri Gautam

एनडीए-एनए 2020 की आंसर-की जारी

सिटी रिपोर्टर| यूपीएससी ने एनडीए-2020 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों पेपर्स के लिए आंसर की जारी की गई है, जिसे कैंडिडेट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने 6 सितंबर को एनडीए-एनए 2020 परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा का रिजल्ट 6 मार्च 2021 को जारी किया गया था।

जून में तय एलसैट अब 29 मई से होगी

सिटी रिपोर्टर| लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल ने जून में होने वाले लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (एलसैट) 2021 को तारीख में बदल दी है। अब यह एग्जाम अलग-अलग स्लॉट्स में 29 मई से आयोजित होगी। इससे पहले परीक्षा का आयोजन 14 जून से किया जाना था। इस बारे में काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि काउंसिल ने सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की तारीखों में क्लैश से बचने के लिए परीक्षा प्री-पोन करने का फैसला किया है। कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 14 मई तक कर सकते हैं।

8 मई को रिमोट मोड में होगी सीएस परीक्षा

सिटी रिपोर्टर| आईसीएसआई ने मई सेशन में होने वाली कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट-2021 की तारीख जारी कर दी है। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट 8 मई को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में आयोजित होगी। इसमें कैंडिडेट्स को घर बैठे या किसी अन्य सुविधाजनक जगह से टेस्ट में शामिल लेने की अनुमति दी है। कैंडिडेट्स, परीक्षा के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मोबाइल, टैबलेट आदि के जरिए परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।

Badri Gautam

बिना सुरक्षा और ट्रेनिंग के अस्पतालों में लगाई शिक्षकों की ड्यूटी

भोपाल। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले दो-तीन माह में 400 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। हाल ही में सीधी के शिक्षक सुरेश जायसवाल का चार दिन तक चले इलाज के बाद कोराना से जब मौत हुई, तब उनकी आरटी पीसीआर की रिपोर्ट निगेटिव आई। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों को बिना सुरक्षा और ट्रेनिंग के अस्पतालों में ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी का परिणाम है कि शिक्षकों की मौत हो रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का सीधी में मामला सामने आया है। शिक्षक जायसवाल का एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पाजीटिव आने पर उन्हें भर्ती कर इलाज किया गया। उसी दिन उनकी आरटी पीसीआर भी कराई थी।

Badri Gautam

जब 10 फीसदी उपस्थिति के निर्देश तो कैसे बुला सकते हैं सभी कर्मचारियों को

भोपाल (आरएनएन)। महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर एक और राज्य सरकार ने समस्त सरकारी कार्यालयों में मात्र 10 प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित की है। वही भोपाल संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रतिदिन शत प्रतिशत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कमिश्नर कार्यालय की इस व्यवस्था के विरोध में सरकारी कर्मचारी खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेनद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य मंत्रालय और सतपुड़ा से लेकर विंध्यांचल सहित संभाग जिला एवं ब्लॉक कार्यालय तक 10 फ़ीसदी उपस्थिति राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य की गई है। उसके बाद भी संभागीय कार्यालय में प्रतिदिन कर्मचारियों की शत.प्रतिशत मौजूदगी दर्ज करवाई जा रही है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष का आरोप है कि जो सेवक ड्यूटी करने नहीं पहुंच रहा है उसको कार्यवाही का भय दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कार्यालय के कई कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। फिर भीआदेश के अनुसार यहां ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है।

Badri Gautam

180 योग प्रशिक्षकों को मिला ऑनलाइन प्रशिक्षण

भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा होम आइसोलेशन में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को स्वस्थ्य रखने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय योग से निरोग कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत राजधानी में पंजीकृत हुए 180 योग प्रशिक्षकों को टेनिंग दी गई है। जो सोमवार से राजधानी में 1800 से अधिक कोविड मरीजों को योगा की टेनिंग देकर हौसला बढ़ाएंगे। योग प्रशिक्षकों को कोविड-19 केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन वेबेक्स और यूट्यूब के माध्यम से दिया गया है। यह कार्यक्रम आयुष और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से संचालित किया जा रहा है।

Badri Gautam

निकटतम शालाओं में जमा होंगी प्री बोर्ड की कॉपियां

भास्कर न्यूज | सतनां

कोरोना महामारी के चलते स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले में संचालित सभी छात्रावास तथा अशासकीय हॉस्टलों को खाली कराने के आदेश जारी किए गए हैं। बीते शैक्षणिक सत्र से राज्य शिक्षा केन्द्र सहित आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास बंद चल रहे हैं। छात्रावासों में रहने वाले 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को स्कूलों से प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पुस्तिकाएं दे दी गई हैं। ओपन बुक प्रणाली से आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं निकटतम शालाओं में जमा कराई जाएंगी। जहां से यह कॉपियां सम्बंधित स्कूल को भेजी जाएंगी।

BadriGautam

जून माह में ऑफलाइन होगी सीएस की परीक्षा

भोपाल। कोविड महामारी के कारण स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में परीक्षाएं या तो रद्द कर दी गई है या स्थगित की जा रही हैं। लेकिन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने स्पष्ट किया है कि जून में सीएस की परीक्षाएं समय पर करवाई जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने भी सीए फाउंडेशन जून परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीएसआई भोपाल चैप्टर की अध्यक्ष सीएस अरविंद तिवारी ने बताया कि फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव व प्रोफेशनल परीक्षाएं 1 से 10 जून तक होंगी।

Badri Gautam

दो हजार प्रोफसरों को दिया गया प्रशिक्षण

मप्र के 516 कॉलेजों में से 473 में प्रभारी प्राचार्य किया पदस्थ

स्टार समाचार भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग प्रोफेसरों की अंतिम वरिष्ठता सूची को जारी नहीं कर सकता है। इसमें जहां सीधी भर्ती और पदोन्नति ने मामला उलझा रखा है। वहीं आरक्षण का प्रतिशत फाइनल नहीं होने के कारण विभाग को प्रोफेसरों को प्राचार्य बनाने में काफी परेशानी आ रही है। इस कारण विभाग ने आरक्षण और वरिष्ठता को नजरअंदाज कर प्रशिक्षण प्राप्त प्रोफेसरों को प्राचार्य बनाएगा। इसके लिए करीब दो हजार प्रोफेसरों को प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग प्रोफेसरों की अंतिम सूची करता है, तो प्रोफेसर हाईकोर्ट में सूची के खिलाफ याचिका दायर कर देते हैं। वहीं आरक्षण लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर छोड़ रखा है।

इसके बाद भी शासन प्रोफेसरों को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाने की गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा है, इसलिए चयनित दो हजार प्रोफेसरों को प्रशासन अकादमी से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब उन्हें प्राचार्य बनाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के 516 यूजी-पीजी कालेज में से सिर्फ 43 प्राचार्य नियमित हैं। इसमें से तीन भोपाल में पदस्थ हैं, जिसमें स्टेट लॉ कालेज में सुधा बैसा और भेल कालेज में मथुरा प्रसाद पदस्थ हैं।

प्रभारी में हो रहे आए दिन विवाद

478 कालेजों में विभाग ने वरिष्ठ प्रोफेसर के अलावा जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया है। इससे कालेजों में आए दिन विवाद होते हैं। वहीं कई कालेजों में वरिष्ठ प्रोफेसर प्रभारी प्राचार्य रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए विभाग को कई वरिष्ठ प्रोफेसरों ने प्रभारी प्राचार्य का पद छोड़ने के लिए आवेदन किए हैं।

Badri Gautam

स्थापना के आठ साल बाद विवि में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद

हिंदी विश्वविद्यालय में डेढ़ दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी भर्ती, रोस्टर जारी कर 21 दिन में मंगाईं आपत्तियां

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

अटल विहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, डेढ़ दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की तैयारी में हैं। इसके लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। रोस्टर में विवि ने आपत्तियां मंगाई हैं। आपत्तियों के निराकरण के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे।

हिंदी विश्वविद्यालय में आठ साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इन आठ सालों में विश्वविद्यालय में 9 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद बढ़ गए हैं। बताया

जाता है कि हिंदी विश्वविद्यालय ने छह प्रोफेसर और तीन एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में परिवर्तित करा लिया है, क्योंकि वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन में 9 ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे, जो अब 18 हो गए हैं। रजिस्ट्रार यशवंत पटेल ने आदेश जारी कर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 21 दिनों का समय दिया है। उम्मीदवार रजिस्ट्रार के नाम से डाक से आपत्तियां भेज सकते हैं।

Badri Gautam

इन विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की होनी है भर्ती

अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास, कृषि विज्ञान, पत्रकारिता एवं संचार, प्रबंधन एवं वाणिज्य, भारतीय दर्शन एवं ज्ञान परंपरा, भौतिक शास्त्र, योग एवं मानव चेतना, रसायन, वनस्पति, विधि, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य, संगणक, हिंदी भाषा एवं अनुवाद, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन तथा प्राणि शास्त्र के एक-एक पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है।

नए सत्र तक नियमित टीचर्स की भर्ती की तैयारी

अभी तक हिंदी विश्वविद्यालय किराए के भवन में चल रहा था। इसकी वजह से

बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई थीं। अब विश्वविद्यालय खुद के भवन में पहुंच गया है। कवर्ड हॉस्टल के साथ यहां पर कम फीस में अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अवश्य ही स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी। रोस्टर जारी कर दिया गया है, ताकि नए सत्र तक नियमित टीचर्स की भर्ती की जा सके।

यशवंत पटेल, रजिस्ट्रार, अटल बिहारी हिंदी विवि, भोपाल